भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1659
उत्तर देने की तारीख 13 दिसम्बर, 2023

स्पेक्ट्रम प्रबंधन

1659. डॉ. मोहम्मद जावेद:
श्री के. सुधाकरन:
श्री टी.एन. प्रथापन:
डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम प्रबंधन से संबंधित जटिल मुद्दों पर राय देने के लिए एक स्थायी समिति गठित की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या स्पेक्ट्रम आवंटन और पुलिस दूरसंचार में तथा आपातकालीन जरूरतों के लिए आवश्यक उपकरण के मामले में पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू) से नीतिगत दिशानिर्देश नहीं होने के बारे में सरकार अवगत है;
(घ) यदि हां, तो डीसीपीडब्ल्यू से नीतिगत दिशानिर्देश के नहीं होने की समस्या को दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकारी एजेंसियों द्वारा स्पेक्ट्रम के उपयोग की निगरानी के लिए उपकरणों की खरीद की स्थिति क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) और (ख) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने जून, 2023 में स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया है। इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों, उद्योग, शिक्षा-जगत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सदस्य शामिल हैं। समिति के अधिदेश में

अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय फ्रीक्वन्सी आवंटन योजना (एनएफएपी) की समीक्षा करना, विश्व रेडियोसंचार सम्मेलन (डब्ल्यूआरसी) के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक समिति (एनपीसी) के कार्यकलाप, स्पेक्ट्रम री-फ़ार्मिंग और री-परपसिंग की आवश्यकता और तरीके, स्पेक्ट्रम के लिए असाइनमेंट/चार्जिंग पद्धति और स्पेक्ट्रम के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक नीतियों/योजना की सिफारिश करना शामिल हैं।

(ग) और (घ) समन्वय निदेशालय, पुलिस वायरलेस (डीसीपीडब्ल्यू), गृह मंत्रालय ने अप्रैल, 2023 में पुलिस दूरसंचार में स्पेक्ट्रम प्रबंधन पर एक नीति तैयार की और सभी केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) को परिचालित की है। इसके अलावा डीसीपीडब्ल्यू राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों की आपातकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेंट्रल स्टोर, दिल्ली तथा चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, गांधीनगर में स्थित इसके 04 क्षेत्रीय स्टोरों में आवश्यक संचार उपकरणों का स्टॉक उपलब्ध है।

(ङ) दूरसंचार विभाग ने सरकारी प्रयोक्ता सहित वायरलेस प्रयोक्ता द्वारा स्पेक्ट्रम के उपयोग की निगरानी के लिए देश भर में 28 निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं। अपनी स्पेक्ट्रम निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए दूरसंचार विभाग समय-समय पर निगरानी उपकरण की खरीद करता है।

*****